cent in India's imports U. S. dollars during April-May 1993 in comparison to corresponding period last year; and

(d) if so, what steps government propose to take to achieve the projected growth rate of imports/exports during the Eighth Plan period (1993-97)?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) As per provisional figures, the exports during April-May 1993, the latest period for which such data are available, have increased to US $ 3458.58 million as compared to US $ 2666.83 million in April-May 92 signifying growth of 29.69%. In the background of emerging trends in export growth in the recent months, the target is considered to be achievable.

(c) The export-import policy announced on 31st March 92 is valid for a period of 5 years and is co-terminus with the Eighth Five Year Plan, 1992-97. The Government have taken Policy initiatives by way of liberalisation of trade which, inter alia, include provision of export linked imports, full convertibility of rupee on trade account, reduction in customs duties and increases in availability of credit at lower rate of interest so as to create an environment which is conducive for export promotion.

556. *[Transferred to 10th August, 1993]*.

Boosting of Indian Exports

557. SHRI SURESH PACHOURI
SHRI IQBAL SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India can double its exports by 1995-96 in case there is a close co-ordination between the Centre and State Governments and the industry as suggested by the experts;

(b) whether Government have agreed to these suggestions; and

(c) if so, to what extent they have agreed to co-ordinate?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (c) It is recognised that close coordination between the Centre and State Governments and industry is necessary for boosting India's exports though the Ministry is not aware of the specific forum of experts which linked such coordination with doubling of exports by 1995-96. The Government is maintaining close contact and coordination on a continuous basis.

The Government has made special efforts to actively involve the state governments in exports efforts by setting up apex export boards/calls. The Government is also having a close interaction with the industry to support its export efforts.

चाय उद्योग पर उपकर लगाया जाना

558. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन**:
श्री राम जेठमलानी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में चाय उद्योग पर उपकर लगाकर कर वसूल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार वसूल की गई राशि की मात्रा प्रत्येक वर्ष कितनी रही;

(ग) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड के माध्यम से उपकर द्वारा प्राप्त इस राशि को चाय का उत्पादन तथा गुणवत्ता में वृध्दि के लिए प्रयुक्त किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो चाय बोर्ड के अन्तर्गत इस प्रयोजन हेतु अनुसंधान-कार्य में कुल कितने संस्थान लगे हुए हैं तथा उनका वार्षिक बजट कितना है; और

(ङ) चाय बोर्ड द्वारा उपकर से प्राप्त धनराशि की कौन-कौन सी मद पर तथा किस-किस अनुपात में आम तौर पर अभी तक खर्च किया गया है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) चाय अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी किस्म की उत्पादित चाय पर उपकर लगाया जाता है। उपकर की वर्तमान दर 8 पैसे प्रति किलो तथा 15 पैसे प्रति किलो है जोकि चाय उत्पादन क्षेत्र पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय पर एकत्रित उपकर निम्नानुसार रहा है:—

वर्ष	एकत्रित उपकर
	(करोड़ रु० में)
1990-91	12.07
1991-92	12.34

1992-93	11.20
	(अनुमानित)

(ग) उपकर से प्राप्त धन का उपयोग चाय बोर्ड द्वारा अनेक कार्यकलापों के लिए किया जाता है जिनमें निर्यात संवर्धन, अनुसंधान और विकास तथा श्रम कल्याण योजनाएं शामिल हैं जिससे कि उत्पादन को बढ़ावा मिले तथा निर्यात में वृद्धि हो।

(घ) कुर्सियांग में स्थित अनुसंधान केन्द्र (दार्जिलिंग चाय अनुसंधान केन्द्र) को छोड़कर, जोकि विशेष रूप से दार्जिलिंग चाय की विशिष्ट समस्याओं की जांच करता है, सीधे चाय बोर्ड के अन्तर्गत कोई अनुसंधान केन्द्र नहीं है। तथापि चाय के क्षेत्र में मुख्य अनुसंधान केन्द्र है: उत्तर पूर्वी भारत में चाय अनुसंधान संस्था तथा दक्षिण भारत में दक्षिणी भारत का संयुक्त बागान मालिक चाय अनुसंधान संस्थान। इसके अतिरिक्त असम कृषि विश्व विद्यालय, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर तथा कलकत्ता विश्व विद्यालय इत्यादी में अनुसंधान क्रियाकलाप भी किये जाते है। पिछले 3 वर्षों के दौरान एकत्रित कुल उपकर में से ऐसे अनुसंधान संस्थानों को चाय बोर्ड द्वारा दी गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:—

	(लाख रु० में)
1990-91	145.78
1991-92	107.56
1992-93	292.43

(ङ) पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर चाय उत्पादन पर लिए गए उपकर की राशि का निम्नानुसार उपयोग किया गया है:—

निर्यात संवर्धन	44%
प्रशासनिक लागत	37%
अनुसंधान और विकास	17%
श्रम कल्याण	2%

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का संवर्धन

559. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र कहां-कहां अवस्थित हैं तथा इनकी स्थापना पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एककों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शत-प्रतिशत व्यापार करने का दायित्व सौंपा गया था;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान इन एककों द्वारा नियोजित मदों की मात्रा तथा मूल्य का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त वर्षों के दौरान उनका कुल उत्पादन कितना रहा; और

(ङ) देश से किये गये कुल निर्यात की तुलना में इन एककों द्वारा किए गए निर्यात की प्रतिशतता क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमरुद्दीन अहमद): (क) जी, हां।

(ख) निर्यात संसाधन जोन काण्डला (गुजरात), बम्बई (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), मद्रास (तमिलनाडु), नोयडा (उ० प्र०), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विशाखापत्तनम (आं० प्र०) में स्थित हैं। अब तक उनके विकास पर 129.74 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) औद्योगिक इकाइयों को अस्वीकृत माल और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री के लिए स्वीकार्य माल को छोड़कर अपने समूचे उत्पादन का निर्यात करना आवश्यक होता है।

(घ) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में सभी निर्यात संसाधन जोनों का कुल निर्यात निम्नलिखित है:—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु०)
1990-91	982.70
1991-92	1117.14
1992-93	1376.31

(ङ) निर्यात संसाधन क्षेत्रों से देश के कुल निर्यात का लगभग 3% भाग निर्यात हुआ है।

Export of Fish

560. SHRI RAMENDRA KUMAR YADAV 'RAVI'
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of fish collected from the states throughout the country for export purpose;

(b) what was the shares of Gujarat and Bihar;

(c) what is the amount of foreign exchange that has been earned through export of fish during the last three years; and

(d) what steps Government propose to take to promote more export of fish?